भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3676

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

रोजगार सृजन और बेरोजगारी के रुझान

3676. श्री किशोरी लाल:

प्रो. सौगत राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और शिक्षित रोजगार की तलाश करने वालों के बीच बढ़ती बेरोजगारी से संबंधित चिंताओं का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बेरोजगारी दर, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान विनिर्माण, कृषि, निर्माण, सेवा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, कौशल भारत मिशन और अन्य रोजगार से जुड़ी पहलों जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ड) क्या सरकार का शिक्षित युवाओं, महिलाओं और पहली बार रोजगार की तलाश करने वालों के बीच बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई नई नीति या रोजगार पैकेज शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 3.6% से घटकर 2025 में 3.1% हो गई है और इसी अवधि के दौरान महिलाओं के लिए यूआर 3.3% से घटकर 3.1% हो गई है। साथ ही, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित यूआर वर्ष 2022 में 10.9% से घटकर वर्ष 2025 में 9.9% हो गई है। इसके अलावा, वर्ष 2022 और वर्ष 2025 से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के शिक्षित व्यक्तियों के लिए यूआर निम्नानुसार है:

बेरोज़गारी दर (% में)		
विवरण	2022	2025
निरक्षर	0.3	0.3
साक्षर एवं प्राथमिक शिक्षा तक	0.8	0.6
पूर्व-माध्यमिक	2.0	1.6
माध्यमिक एवं उससे ऊपर	8.0	6.5
समस्त	3.6	3.1

स्रोत : पीएलएफएस, एमओएसपीआई

इसके अलावा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2022 में 54.1% से बढ़कर वर्ष 2025 में 57.4% हो गया है और देश में इसी अवधि के दौरान अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 52.8% से बढ़कर 55.7% हो गई है।

साथ ही, वर्ष 2022 और 2025 के दौरान पीएलएफएस रिपोर्टों से अनुमानित व्यापक उद्योग श्रेणियों के हिसाब से सामान्य स्थिति के आधार पर कामगार का प्रतिशत वितरण निम्नानुसार है:

विवरण	2022	2025
विनिर्माण	11.2%	12.1%
कृषि	45.5%	43.0%
निर्माण	13.4%	12.0%
अन्य सेवाएँ	11.5%	13.1%

स्रोत : पीएलएफएस, एमओएसपीआई

पीएलएफएस रिपोर्ट में वर्षवार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार, क्षेत्र-वार और उद्योग-वार जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की चुनिंदा योजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगार का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) भी चला रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है जिसका उद्देश्य उद्यमों को औपचारिक रूप देना, सरकारी सहायता तक पहुँच का विस्तार करना और एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल में कुल 8.9 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए हैं जिसमें उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) भी शामिल है जिससे देशभर में 39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके अलावा, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। पीएमवीबीआरवाई एक मांग-संचालित योजना है। देश में इस योजना के कार्यान्वयन के बाद से जून, 2026 तक, भाग “क” के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले 13.18 लाख कर्मचारियों को 744.58 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है, जबकि योजना

के भाग “ख” के तहत 67,369 लाभार्थी प्रतिष्ठानों को 2,068.84 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 10.08.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3676 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में केंद्रीय योजनाओं में रोजगार सृजन/लाभार्थी

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2023-24	2024-25	2025-26
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (सृजित रोजगार की अनुमानित संख्या)	802062	537372	598446
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) (सृजित मानव दिवस- लाख में)	30854.86	28617.08	22812.1
3	प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना	पीएम इंटर्नशिप योजना का पहला दौर - साझेदार कंपनियों ने उम्मीदवारों को 82000 से अधिक इंटर्नशिप ऑफर दिए। पीएम इंटर्नशिप योजना का दूसरा दौर- साझेदार कंपनियों ने उम्मीदवारों को 83000 से अधिक इंटर्नशिप प्रस्ताव दिए		
4	स्किल इंडिया मिशन- पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित	पीएमकेवीवाई 1.0		19,86,016
		पीएमकेवीवाई 2.0		1,10,00,708
		पीएमकेवीवाई 3.0		7,37,502
		पीएमकेवीवाई 4.0		28,17,453
5	प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (खातों की संख्या)	66,777,013	54,661,648	50,026,549
6	प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) (लाभार्थियों की संख्या)	*28,94,722*	*4,24,656*	*6,66,159*
7	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या) दिनांक 10.7.2026 तक	161230	98295	77034
8	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या) दिनांक 30.10.2025 तक	350272	467259	201108
9	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) (कुशल प्रशिक्षित नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या)*	54,717	5,082 30.09.2024 तक	-

*योजना 30 सितंबर, 2024 को समाप्त हुई

स्रोत: संबंधित मंत्रालय